



क्रमांक : 4092 /अका./वि.प./2015

रायपुर, दिनांक : 10/07/2015

विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 17 जुलाई, 2015 दिन-शुक्रवार
अपरान्ह 3:00 बजे कुलपति कक्ष में आयोजित बैठक की विषय-सूची

01. विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक, दिनांक 03.07.2014 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान करना। (पृष्ठ क्र. 01 से 03 तक)
टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।
02. विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक, दिनांक 03.07.2014 के पालन प्रतिवेदन का सूचना ग्रहण करना।
03. उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को SAP (Special Assistance Programme) के लिए पद की स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रस्ताव सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। (पृ. 4 से 6 तक)
टीप : पत्र क्र. 11/स्था./सा.प्रशा./15 दिनांक 01.01.2015 की छायाप्रति संलग्न।
04. उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को अंग्रेजी अध्ययनशाला के स्थापना के लिए पद की स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रस्ताव सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। (पृ. क्र. 07 से 14 तक)
टीप : पत्र क्र. 936/सा.प्रशा./2015 दिनांक 17.03.2015 की छायाप्रति संलग्न।
05. उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को स्वामी विवेकानंद स्मृति तुलनात्मक धर्म दर्शन एवं योग अध्ययनशाला के प्रस्ताव अनुसार पद की स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रस्ताव सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। (पृ. क्र. 15 से 25 तक)
टीप : पत्र क्र. 2290/स्था./सा.प्रशा./2015 दिनांक 09.07.2015 की छायाप्रति संलग्न।
06. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत में सामाजिक विचारक अवचेतना के संबंध में आमंत्रित प्रस्ताव सूचनार्थ प्रस्तुत। (पृ. क्र. 26 से 35 तक)
टीप : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सामाजिक विचारक की अवचेतना निम्नलिखित सामाजिक विचारक एवं नेता, Buddha, Gandhi, Nehru and Ambedkar के विचारों पर अध्ययन हेतु 12वीं पंचवर्षीय वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया।

बौद्ध धर्म के अध्ययन हेतु पाली एवं संस्कृत भाषा में सुविधा युक्त क्षेत्र तथा अध्ययन केन्द्र को प्राथमिकता या अन्य विभाग जैसे - दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र एवं प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति विभागों के परीक्षण के उपरांत इस योजना की स्वीकृति दिया जा सकता है। साथ ही अन्य ऐसे विभाग Innovative Ideas के साथ कार्यरत है, उन्हें भी प्राथमिकता दी जा सकती है। वित्तीय सहायता 12वीं पंचवर्षीय योजना के Guideline के अनुसार देय होगा। Guide Line की छायाप्रति संलग्न।

07. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा **Guidelines for e-Content Development of Project, Submission for Assistance From UGC Under NME-ICT** के अन्तर्गत "e-PG Pathshala" संबंधी योजना सूचनार्थ प्रस्तुत। (पृ. क्र. 36 से 47 तक)

टीप : विश्वविद्यालय अनुदान की "e-PG Pathshala" कार्यक्रम के अन्तर्गत अध्ययन-अध्यापन को लाभकारी बनाने हेतु A Project Under National Mission of Education through ICT (NME-ICT) के माध्यम से Connectivity के लिए Computer अधोसंरचना हेतु 32 हजार महाविद्यालयों एवं 550 विश्वविद्यालयों का चयन किया जाना है। NME-ICT मुख्यतः निम्न तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है -

- e-Content Development
- Infrastructure Development
- Social Impact

e-PG Pathshala के अन्तर्गत MHRD द्वारा शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्देश्यों की ICT के माध्यम से पूर्ण करने पत्र क्रमांक F.B-13/2011-TEL dated 29th September 2011 के द्वारा 77 स्नातकोत्तर विषयों में e-content निर्माण करने हेतु वित्तीय सहायता यू.जी.सी. को स्वीकृत किया है। इसके अनुसार विश्वविद्यालय में कार्यवाही कर प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

08. बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। (पृ. क्र. 48 से 52 तक)

टीप : कार्यालयीन टीप संलग्न।

09. सहायक फ़ैकल्टी के पेनल (**Guidelines for Empanelment of Adjunct Faculty in Universities and College**) के निर्धारण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त **Guideline** पर विचार करना। (पृ. क्र. 53 से 59 तक)

टीप : कार्यालयीन टीप संलग्न।

10. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।



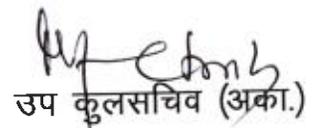
कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 4093 / अका. / वि.प. / 2015

रायपुर, दिनांक : 10/07/2015

प्रतिलिपि :

- विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड के समस्त सदस्यों को।
- वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण।
- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 714 / अका./ वि.प./ 2014

रायपुर, दिनांक : 9 / 07 / 2014

विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक गुरुवार, दिनांक 03.07.2014 को अपराह्न 3.00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थिति हुए :-

1. प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	—	अध्यक्ष
2. प्रो. (श्रीमती) स्वर्णलता सराफ	—	सदस्य
3. प्रो. भगवंत सिंह	—	सदस्य
4. प्रो. सी.डी. अगासे	—	सदस्य
5. प्रो. ए.के. श्रीवास्तव	—	सदस्य
6. प्रो. ओ.पी. चन्द्राकर	—	सदस्य
7. प्रो. एस.सी. नैथानी	—	सदस्य
8. प्रो. विभूति राय	—	सदस्य
9. प्रो. मिताश्री मित्रा	—	सदस्य
10. प्रो. के.के. घोष	—	सदस्य
11. प्रो. ए.के. गुप्ता	—	सदस्य
12. प्रो. शुक्ला बनर्जी	—	सदस्य
13. डॉ. पुलोक के. मुखर्जी	—	सदस्य
14. डॉ. श्रीनिवासन नरसिम्हन	—	सदस्य
15. डॉ. ए.टी. दाबके	—	सदस्य
16. डॉ. एस.के. पाटिल	—	सदस्य
17. प्रो. ए.के. पति	—	सदस्य
18. श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	—	सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गए :-

01. विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक, दिनांक 10.07.2013 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : सम्पुष्टि प्रदान की गई।

02. विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक, दिनांक 10.07.2013 के पालन प्रतिवेदन का सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक, दिनांक 10.07.2013 के पालन प्रतिवेदन का सूचना ग्रहण की गई।

03. DST के द्वारा स्वीकृत एन.सी.एन.आर. प्रोजेक्ट के द्वारा किये जा रहे कार्यों की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : DST के द्वारा स्वीकृत एन.सी.एन.आर. प्रोजेक्ट के द्वारा किये जा रहे कार्यों की सूचना ग्रहण किया गया।

04. विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के अन्तर्गत शासन को भेजे गये प्रस्ताव (IDP) अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
निर्णय : विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के अन्तर्गत शासन को भेजे गये प्रस्ताव (IDP) का अनुमोदन किया गया।
05. विश्वविद्यालय द्वारा सेंटर फार बेसिक साइंस की स्थापना के लिए शासन को भेजे गये प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
निर्णय : विश्वविद्यालय द्वारा सेंटर फार बेसिक साइंस की स्थापना के लिए शासन को भेजे गये प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
06. अध्यापक शिक्षण संस्थान के लिए पदों के सृजन हेतु भेजे गये प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
निर्णय : अध्यापक शिक्षण संस्थान के लिए पदों के सृजन हेतु भेजे गये प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
07. पर्यावरण विज्ञान विभाग के लिए शासन को पदों की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
निर्णय : पर्यावरण विज्ञान विभाग के लिए शासन को पदों की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
08. भौतिकी विभाग द्वारा एम.एस.सी. पाठ्यक्रम में Space Science एवं Nano Science का प्रश्नपत्र शामिल किए जाने संबंधी कार्यवाही सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
निर्णय : भौतिकी विभाग द्वारा एम.एस.सी. पाठ्यक्रम में Space Science एवं Nano Science का प्रश्नपत्र शामिल किए जाने संबंधी कार्यवाही की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।
09. सत्र 2013-14 में DST एवं FIST के द्वारा स्वीकृत नये प्रोजेक्ट की जानकारी सूचनार्थ प्रस्तुत।
निर्णय : DST एवं FIST के द्वारा स्वीकृत प्रोजेक्ट की सूचना ग्रहण की गई।
10. ISRO के EDUSAT के माध्यम E-learning एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों से Connectivity के प्रस्ताव पर विचार करना।
निर्णय : ISRO के EDUSAT के माध्यम E-learning एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों से Connectivity के प्रस्ताव के अनुसार कार्यवाही हेतु अनुशंसा की गई।

11. विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा एवं प्रशासनिक कार्यों का आटोमेशन करने की कार्यवाही की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा एवं प्रशासनिक कार्यों का आटोमेशन करने के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा की जा रही कार्यवाही की सूचना ग्रहण किया गया।

12. इंजीनियरिंग स्नातक छात्रों को एम.एस-सी. गणित में प्रवेश हेतु Bridge Course की अनिवार्यता पर विचार करना।

निर्णय : इंजीनियरिंग स्नातक छात्रों को एम.एस-सी. गणित में प्रवेश हेतु Bridge Course के माध्यम से एम.एस-सी. गणित में प्रवेश संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

01. Choice Based Credit System के पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु संकायाध्यक्षों एवं अध्ययन मण्डल के अध्यक्षों की संयुक्त बैठक आयोजित कर शीघ्र पाठ्यक्रम तैयार किया जावे।

02. शोध पत्रों के प्रकाशन में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रत्येक विषय में Peer Reviewed Journal/Referred Journal/Index Factor की सूची, संकायाध्यक्ष, अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष की समिति गठित कर तैयार किया जावे।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष

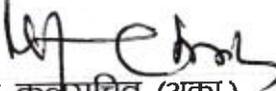

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 715 /अका./वि.प./2014

रायपुर, दिनांक : 9 /07/2014

प्रतिलिपि:-

1. विद्या सम्बन्धी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड के समस्त सम्माननीय सदस्यों को।
2. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
3. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)

(3)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

(4)

विषय:- उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को SAP (Special Assistance Programme) के लिये पद की स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रस्ताव सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

/// टीप ///

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मार्गदर्शिका के अनुसार विश्वविद्यालय के ऐसे विभाग SAP स्कीम के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित पद संख्या नहीं होने के कारण पद स्वीकृति हेतु प्रस्ताव कार्यालयीन पत्र क्रमांक 11/स्था./सा.प्रशा./15 दिनांक 01.01.2015 के द्वारा आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित किया गया है। (पदनाम, पद संख्या एवं अध्ययनशाला का विवरण उपरोक्त उल्लेखित पत्र में संलग्न है)

कार्यालय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/ 11 /स्था./सा.प्रशा./2015

रायपुर, दिनांक 01/01/2015

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
ब्लाक सी- 30, द्वितीय तल,
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

विषय:- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के Special Assistance Programme के अनुसार पदों की स्वीकृती के संबंध में।

महोदय,

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मार्गदर्शिका के अनुसार विश्वविद्यालय के ऐसे विभाग SAP स्कीम के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित पद संख्या प्रोफेसर 01 पद, एसोसिएट प्रोफेसर 02 पद तथा असिस्टेंट प्रोफेसर 03 पद होने पर ही केन्द्रीयकृत वित्तीय संस्थान से वित्तीय सहयोग हेतु प्रस्ताव जमा कर सकते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मार्गदर्शिका के अनुसार SAP स्कीम के अंतर्गत यदि विश्वविद्यालय के विभाग द्वारा प्रस्ताव विभिन्न वित्तीय संस्थान को प्रेषित किये जाते हैं तथा विभिन्न वित्तीय संस्थान से आर्थिक सहयोग प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय की स्थिति सुदृढ़ होगी तथा आगामी नेक मूल्यांकन में विश्वविद्यालय को उच्च श्रेणी प्राप्त करने में सहायक होगा। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग SAP स्कीम के अनुसार पदों की स्वीकृती आवश्यक है।

वर्तमान में इस विश्वविद्यालय के निम्नलिखित विभाग ऐसे हैं- जो SAP स्कीम के तहत प्रस्ताव जमा करने में असमर्थ है, क्योंकि इन विभागों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा SAP स्कीम के तहत निर्धारित पद स्वीकृत नहीं है।

क्रं.	विभाग	पदों की वर्तमान स्थिति			पदों की आवश्यकता (कमी)		
		प्रोफेसर	एसोसिएट प्रोफेसर	असिस्टेंट प्रोफेसर	प्रोफेसर	एसोसिएट प्रोफेसर	असिस्टेंट प्रोफेसर
1	2	3	4	5	6	7	8
01	प्राचीन भारतीय इतिहास	01	01	01	-	01	02
02	इतिहास	01	02	02	-	-	01
03	शारीरिक शिक्षा	01	-	02	-	02	01
04	ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान	-	01	03	01	01	-
05	अंग्रेजी	-	-	-	01	02	03
06	बायो कैमिस्ट्री	-	-	-	01	02	03
07	माइक्रो बायोलॉजी	-	-	-	01	02	03

उपरोक्त आवश्यक शैक्षणिक पदों का व्ययभार निम्नानुसार है:-

क्रं.	पदनाम	पद संख्या	वेतनमान	मासिक वेतन	कुल वार्षिक वेतन
1	प्रोफेसर	04	37400-67000+AGP10000	115407x4 = 461628	5539536
2	एसोसिएट प्रोफेसर	10	37400-67000+AGP 9000	112989x10=1129890	13558680
3	असिस्टेंट प्रोफेसर	13	15600-39100+AGP 6000	53012x13= 689156	8269872
योग		27		2280674	27368088

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मार्गदर्शिका के अनुसार SAP स्कीम के तहत पदों की स्वीकृति नितांत आवश्यक है।

अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मार्गदर्शिका के अनुसार SAP स्कीम के तहत विभिन्न वित्तीय संस्थान से आर्थिक सहयोग प्राप्त किए जाने के लिए उपरोक्त उल्लेखित विभागों के लिए कॉलम 6, 7 एवं 8 में उल्लेखित अनुसार प्रोफेसर 01, एसोसिएट प्रोफेसर 02 एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के 03 पदों की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

संलग्न:- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मार्गदर्शिका।

आदेशानुसार


(के.के.चन्द्राकर)
कुलसचिव




पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विषय:- उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को अंग्रेजी अध्ययन शाला की स्थापना के लिये पद की स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रस्ताव सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

/// टीप ///

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में साहित्य एवं भाषा अध्ययन शाला के अंतर्गत अंग्रेजी पाठ्यक्रम का अध्यापन हो रहा है, किन्तु अंग्रेजी विषय में एक भी नियमित शिक्षक न होने के कारण अध्ययन एवं अनुसंधान की गतिशीलता अवरूद्ध है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजी अध्ययनशाला की स्थापना एवं प्रोफेसर 01 पद, एसोसिएट प्रोफेसर 02 पद एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के 04 पदों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव कार्यालयीन पत्र क्रमांक 936/सा.प्रशा./2015 दिनांक 17.03.2015 के द्वारा आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर को प्रेषित किया गया है।

कार्यालय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर छ.ग.

8

Phone No. 0771-2262587 Website: prsu.ac.in, Email- adm.prsu@yahoo.com

क. / 936 / सा.प्रशा. / 2015

रायपुर, दिनांक 17/03/2015

प्रति,

, आयुक्त,

उच्च शिक्षा विभाग,

ब्लॉक-सी-30, तृतीय तल,

इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ. ग.)

विषय:- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में अंग्रेजी अध्ययनशाला के स्थापना हेतु।

संदर्भ:- अंग्रेजी अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भानुसार लेख है कि पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में साहित्य एवं भाषा विज्ञान अध्ययनशाला के अंतर्गत सन् 1991 से अंग्रेजी में पाठ्यक्रम का अध्यापन हो रहा है किंतु इस हेतु अंग्रेजी विषय में एक भी नियमित शिक्षक न होने के कारण अध्ययन एवं अनुसंधान की गतिशीलता अवरुद्ध है। इसका विपरीत प्रभाव छत्तीसगढ़ राज्य की युवा पीढ़ी पर पड़ रहा है जो न केवल अध्ययन, अनुसंधान बल्कि अभिव्यक्ति के क्षमता के मामले में भी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ जाता है। पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय जिस पर राज्य में उच्च शिक्षा में नेतृत्व प्रदान करने का अहम दायित्व है अब अंग्रेजी विषय में अध्ययन, अनुसंधान हेतु एक स्वतंत्र अद्योसंरचना विकसित करना उसकी अनिवार्यता बन चुकी है।

अतः आपसे निवेदन है कि संलग्न प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए विश्वविद्यालय में अंग्रेजी अध्ययनशाला के स्थापना हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रस्तावित पदों की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

कुलसचिव

पृक्र/937/सा.प्रशा./2015

रायपुर, दिनांक 17/03/2015

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर छ.ग. को सूचानार्थ।

उपकुलसचिव (सा. प्रशा.)

छत्तीसगढ़ शासन

के समक्ष

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में

अंग्रेजी अध्ययनशाला

स्थापना

हेतु प्रस्ताव



आमानाका, जी. ई. रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़-492010

वेबसाइट : www.prsu.ac.in

अंग्रेजी अध्ययनशाला स्थापना हेतु विस्तृत प्रस्ताव

1. विश्वविद्यालय से संबंधित जानकारी:
 - अ. विश्वविद्यालय का नाम : पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
 - ब. पता : आमानाका जी. ई रोड, रायपुर-492010
जिला : रायपुर
राज्य : छत्तीसगढ़
 - स. वेबसाइट का पता : www.prsu.ac.in
 - द. कुलपति : प्रो० एस०के० पाण्डेय, कुलपति (proskp@gmail.com)
दूरभाष : 91-771-2262857(फोन), 91-771-2263439 (फैक्स)
94242-00857 (मो०)
 - य. कुलसचिव : श्री कृष्ण कुमार चन्द्राकर
दूरभाष : 91-771-2262540 (फोन), 91-771-2262818(फैक्स)
94255-22023 (मो०)
2. विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष : 1 मई 1964
3. नैक मूल्यांन : 'बी' ग्रेड
4. अध्ययन संकायों की संख्या : 09
5. अध्ययन शालाओं की संख्या : 27
6. साहित्य अध्ययनशाला के अन्तर्गत एम०ए (अंग्रेजी) पाठ्यक्रम का विवरण :-
 - अ. एम. ए. (अंग्रेजी) पाठ्यक्रम का प्रारंभिक वर्ष - 1991
 - ब. विगत पांच वर्षों में एम.ए. (अंग्रेजी) पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों का विवरण :

क्र०	सत्र	सीट	पंजीकृत	उत्तीर्ण
1	2009-10	30	30	12
2	2010-11	30	29	23
3	2011-12	30	22	13
4	2012-13	30	30	21
5	2013-14	30	27

स. विगत पांच वर्षों में डिप्लोमा इन इंग्लिश पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों का विवरण:

क्र०	सत्र	सीट	पंजीकृत	उत्तीर्ण
1	2009-10	30	15	07
2	2010-11	30	13	04
3	2011-12	30	15	10
4	2012-13	30	09	07
5	2013-14	30	13	08

द. विगत पांच वर्षों में एम०फिल (अंग्रेजी) पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों का विवरण:

क्र०	सत्र	सीट	पंजीकृत	उत्तीर्ण
1	2009-10	10	10	07
2	2010-11	10	10	09
3	2011-12	10	08	07
4	2012-13	10	10	10
5	2013-14	10	09	03

य. विगत पांच वर्षों में अंग्रेजी विषय में पी-एच.डी उपाधि प्राप्तकर्ताओं का विवरण:

क्र०	सत्र	पी-एच.डी उपाधि प्राप्त कर्ताओं की संख्या
1	2010	02
2	2011	03
3	2012	02
4	2013	02
5	2014	05

7. विगत पांच वर्षों में अंग्रेजी विषय से संबंधित शैक्षणिक एवं अनुसंधान कार्यक्रमों का आयोजन:

कार्यक्रम	राष्ट्रीय	अंतर्राष्ट्रीय
सेमीनार	02	—
वर्कशॉप	01	01
रिफ्रेशर कोर्स	02	—
व्याख्यान	06	—

8. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में विगत पांच वर्षों में एम. ए. अंग्रेजी पाठ्यक्रम की परीक्षा से संबंधित विवरण :

वर्ष	सम्मिलित	उत्तीर्ण
2010	586	490
2011	1014	628
2012	1122	1011
2013	1037	982
2014	1289	994

9. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में विगत पांच वर्षों में अंग्रेजी विषय में पी. एच. डी. उपाधि प्राप्त करने वाले छात्रों के विवरण :

वर्ष	संख्या
2010	12
2011	06
2012	07
2013	17
2014	05

10. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में अंग्रेजी विषय में अनुसंधान केन्द्रों की संख्या — 06
11. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में अंग्रेजी विषय में कार्यरत अंग्रेजी विषय की शिक्षकों की संख्या — 75

12. अंग्रेजी पाठ्यक्रम संचालित करने वाले पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों की संख्या-20

13. विश्वविद्यालय में उपलब्ध अंग्रेजी विषय से संबंधित पाठ्य पुस्तक एवं शोध पत्रिका का विवरण:

अ.	पाठ्य पुस्तक	-	1046
ब.	शोध पत्रिका	-	01
स.	अंतर्राष्ट्रीयशोध पत्रिकाएँ (ऑनलाईन)	-	780

14. पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में अंग्रेजी अध्ययनशाला स्थापित किये जाने का औचित्य: सर्वविदित है कि अंग्रेजी साहित्य एवं भाषा का अपने आप में महत्व के अलावा ज्ञान विज्ञान से संबंधित अध्ययन-अनुसंधान के विकास में भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। दुर्भाग्य यह है कि स्थापना के तत्काल बाद पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में जहाँ अंग्रेजी अध्ययनशाला का अलग से सृजन किया जाना था वह नहीं हो सका, और वर्ष 1967-68 के दौर में समूचे देश में उभरे अंग्रेजी विरोधी आंदोलन के दबाव में बगैर विकल्प का निर्माण किए प्रादेशिक शिक्षा में से अंग्रेजी विषय को हटा दिया गया। इसका खामियाजा ना केवल समूचे प्रदेश को बल्कि समूचे युवा पीढ़ी को भुगतना पड़ा। 1991 में किसी तरह विश्वविद्यालय में भाषाविज्ञान अध्ययनशाला के अंतर्गत अंग्रेजी विषय में अध्ययन की शुरुवात हुई किंतु आज तक इसमें बगैर नियमित शिक्षकों के अध्ययन, अध्यापन व अनुसंधान कार्य हो रहा है। इसका परिणाम यह है कि पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय जो कि समूचे प्रदेश में उच्च शिक्षा को नेतृत्व प्रदान करता है अंग्रेजी विषय में पिछड़ जाता है।

राज्य शासन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अंग्रेजी में अध्ययन अनुसंधान की गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के सात पद, भवन, साहित्य आदि के लिए आवश्यक अनुदान स्वीकृत करे ताकि छत्तीसगढ़ के युवाओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने तथा अंग्रेजी में अभिव्यक्ति की क्षमता को पुष्ट करने का ठोस आधार बने।

15. अंग्रेजी अध्ययन शाला के लिए आवश्यक अनुदान :

(अ). आवर्ती अनुदान :

पद	संख्या	वेतन	अनुमानित मूल वेतन प्रतिवर्ष
1. प्रोफेसर	1	बेसिक वेतन-37400-67000 +AGP 10000	1,00,315.00X12 =12,03,780.00
2. एसोसिएट प्रोफेसर	2	बेसिक वेतन-37400-62000 +AGP 9000x2	98215.00X2X12 =23,57,160.00
3. असिस्टेंट प्रोफेसर	4	बेसिक वेतन-15600-39100 +AGP 9000x4	46135.00X4X12 =22,14,480.00
कुल पद	7	6 वें वेतन आयोग के नियमानुसार	57,75,420.00

(ब). अनावर्ती अनुदान :

क्र०	सुविधाएँ	सत्र	अनुमानित व्यय
1	भवन		19500000.00
2	फर्नीचर		04000000.00
3	उपकरण(कम्प्यूटर, फर्नीचर, एल. सी. डी., आदि)		02500000.00
4	लैंग्वेज लैब		03000000.00
कुल रूपये			29000000.00

Sheel Shamma

17-03-2015

डा. (वसिमाती) शैल शर्मा

प्रोफेसर एवं अध्यक्ष

साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला,

पं. रवीशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर.



कुलसचिव
(हस्ताक्षर मुहर सहित)

5



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

15

विषय:- उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को स्वामी विवेकानंद स्मृति तुलनात्मक धर्म, दर्शन एवं योग अध्ययन शाला के प्रस्ताव अनुसार पद की स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रस्ताव सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

टीप

स्वामी विवेकानंद स्मृति तुलनात्मक धर्म, दर्शन एवं योग अध्ययनशाला के अंतर्गत योग से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित है।

अध्यक्ष, स्वामी विवेकानंद स्मृति तुलनात्मक धर्म, दर्शन एवं योग अध्ययनशाला के प्रस्ताव अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर 01, योग अनुदेशक (पुरुष) 01, योग अनुदेशक (महिला) 01, योग सहायक 01 पद कुल 04 पदों की स्वीकृति हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2290/स्था./सा.प्रशा./2015 दिनांक 09.07.2015 के द्वारा आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित किया गया है।

कार्यालय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 2290/स्था./सा.प्रशा./2015
प्रति,

रायपुर, दिनांक 09/07/2015

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
ब्लाक सी- 30, तृतीय तल,
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

विषय :- स्वामी विवेकानन्द स्मृति तुलनात्मक धर्म, दर्शन एवं योग अध्ययन शाला में योग शिक्षक/प्रशिक्षक पद-स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि योग भारतीय शिक्षा व्यवस्था एवं संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर योग अध्ययन एवं अध्यापन/प्रशिक्षण की तीव्र मांग हो रही है। व्यक्ति एवं मानव समाज के समग्र एवं संतुलित विकास के लिए योग शिक्षा अपरिहार्य है।

योग शिक्षा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूर्णतः रोजगारोन्मुखी शिक्षा मिश्र हो रही है। केन्द्र एवं राज्य सरकारों की विशेष घोषणाओं के फलस्वरूप विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय संस्थानों एवं अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों में योग शिक्षा के विविध पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

वर्तमान में स्वामी विवेकानन्द स्मृति तुलनात्मक धर्म, दर्शन एवं योग अध्ययन शाला में योग एवं अनुप्रयुक्त दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर, पी.जी. डिप्लोमा इन योग एजुकेशन एण्ड फिलॉसफी, योग शिक्षा एवं दर्शन शास्त्र में प्रमाण-पत्र, तुलनात्मक धर्म एवं दर्शन शास्त्र में एम.फिल. एवं दर्शन शास्त्र एवं योग में पी.-एच.डी. आदि पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है।

अतः आपसे निवेदन है कि संलग्न प्रस्ताव पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानन्द स्मृति तुलनात्मक धर्म, दर्शन एवं योग अध्ययन शाला में प्रस्ताव अनुसार योग शिक्षक/प्रशिक्षक पदों की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ.क्रमांक 2291/स्था./सा.प्रशा./2015
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 09/07/2015

1. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रपिप्त।

उप कुलसचिव (प्रशा.)

छत्तीसगढ़ शासन

के समक्ष

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

के

स्वामी विवेकानन्द स्मृति तुलनात्मक धर्म, दर्शन एवं योग अ.शा.

में

योग शिक्षक / प्रशिक्षक पद-स्वीकृति हेतु

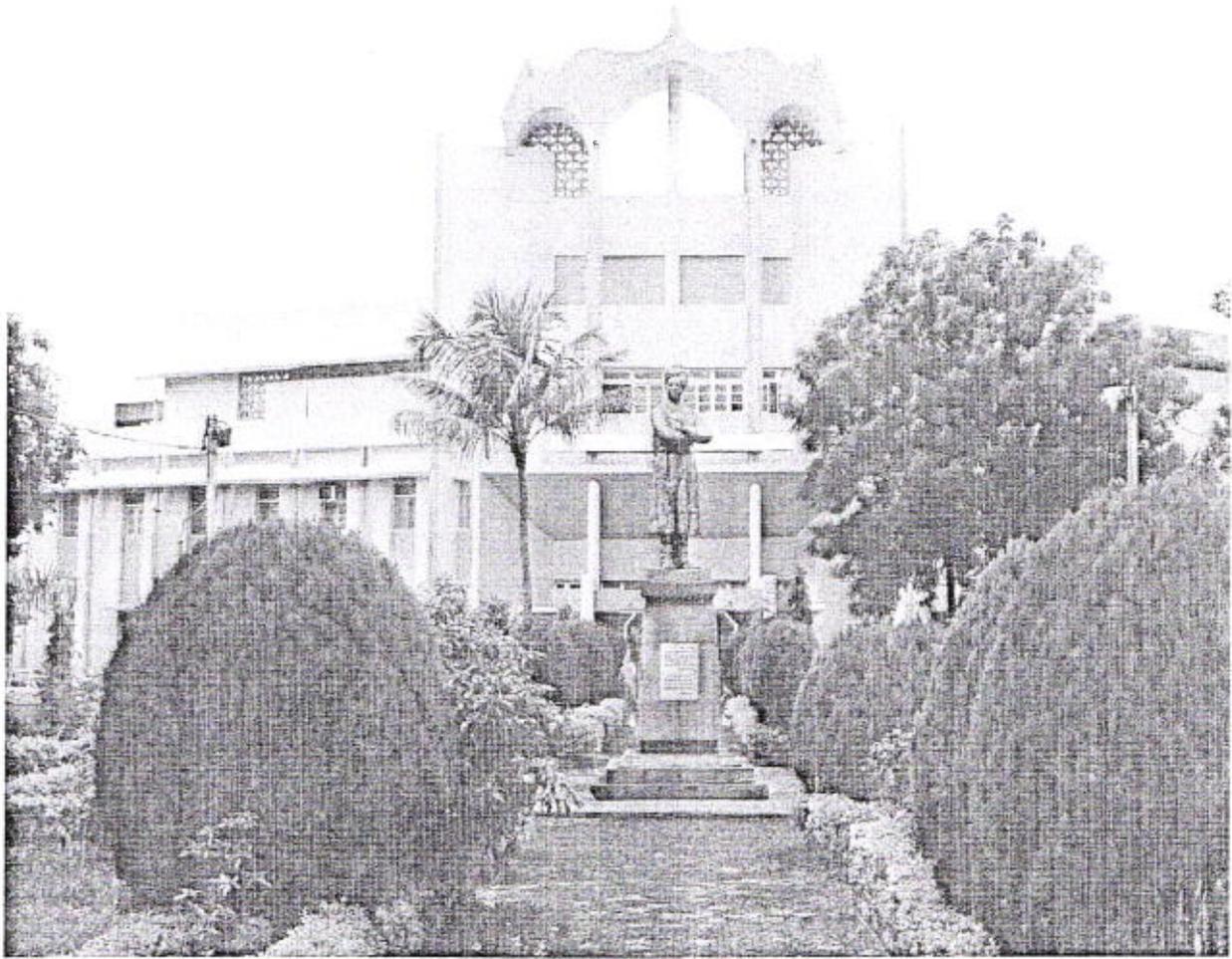
प्रस्ताव



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,

आमानाका, जी.ई.रोड, रायपुर-492010 (छत्तीसगढ़)

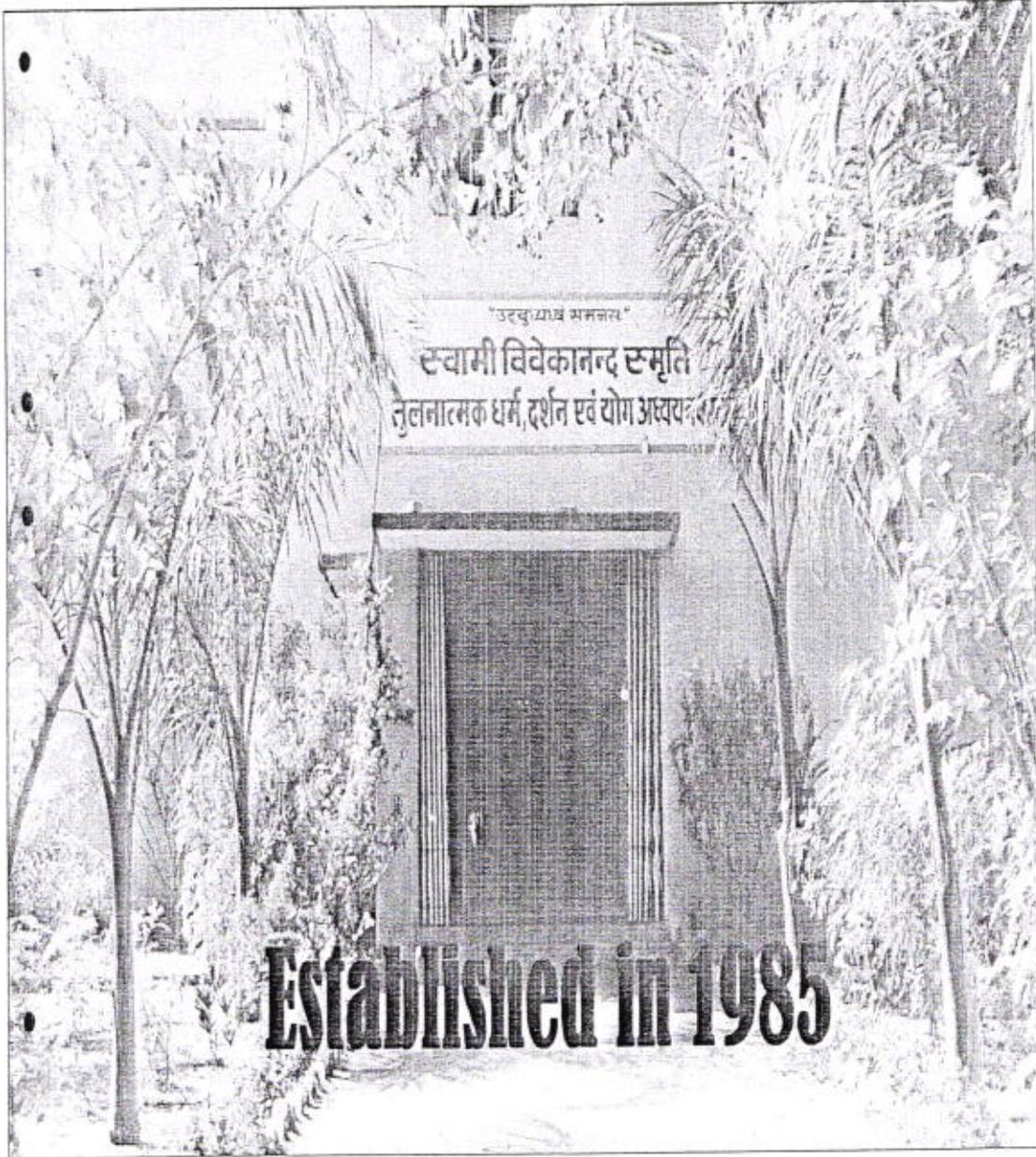
वेबसाइट : www.prsu.ac.in



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये



Swami Vivekanand Memorial SOS in Comparative Rel., Philosophy & Yoga



-04-

स्वामी विवेकानन्द स्मृति तुलनात्मक धर्म, दर्शन एवं योग
अध्ययनशाला में योग शिक्षक-प्रशिक्षक पदों की स्वीकृति
सम्बन्धी प्रस्ताव-

I - विश्वविद्यालय

1. अ. विश्वविद्यालय का नाम : पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
 ब. पता : आमानाका जी.ई.रोड, रायपुर-492010
 जिला : रायपुर
 राज्य : छत्तीसगढ़
- स. वेबसाइट का पता : www.prsu.ac.in
 द. कुलपति : प्रो. एस.के. पाण्डेय, (proskp@gmail.com)
 दूरभाष : 91-771-2262857 (फोन), 91-771-2263439 (फैक्स)
 94242-00857 (मो.)
- य. कुलसचिव : श्री कृष्ण कुमार चन्द्राकर
 दूरभाष : 91-771-2262540(फोन), 91-771-2262818 (फैक्स)
 94255-22023 (मो.)
2. विश्वविद्यालय का स्थापना वर्ष : 01 मई 1964
3. नैक मूल्यांकन : 'बी' ग्रेड (CGPA = 2.62)
4. अध्ययन संकायों की संख्या : 09
5. अध्ययन शालाओं की संख्या : 27

II - योग पाठ्यक्रम की समकालीन उपादेयता:

योग भारतीय शिक्षा व्यवस्था एवं संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर योग अध्ययन एवं अध्यापन/प्रशिक्षण की तीव्र माँग हो रही है। व्यक्ति एवं मानव समाज के समग्र एवं संतुलित विकास के लिए योग शिक्षा अपरिहार्य है। समकालीन वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक एवं वैश्विक स्तर की ज्वलंत समस्याओं का समाधान योग में विद्यमान है। योग एक मात्र ऐसी उपचार पद्धति (Pathy) है जो मनुष्य की मनो-शारीरिक संरचना को स्वस्थ रखने के लिए सावधानी एवं उपचार (Precaution & Treatment) दोनों है। मूल्यशिक्षा के रूप में योग की उपादेयता और भी बढ़ जाती है। विश्व समुदाय जगत गुरु भारत की ओर योगानुदान हेतु आशापूर्ण दृष्टि से निहार रहा है। भारत सरकार के विशेष प्रयास एवं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के यू.एन. के मंच से प्रतिवर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस मनाने की घोषणा एवं विश्व के शताधिक देशों सहित यूनेस्को आदि की विनम्र स्वीकृति योग की उपादेयता का ज्वलंत प्रमाण है।

योग शिक्षा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूर्णतः रोजगारोन्मुखी शिक्षा सिद्ध हो रही है। केन्द्र एवं राज्य सरकारों की विशेष घोषणाओं के फलस्वरूप विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, चिकित्सालयों, सेना एवं पुलिस विभाग में राष्ट्रीय संस्थानों एवं अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों में योग शिक्षा के विविध पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं और नये विभाग स्थापित हो रहे हैं।

-06-

इस प्रकार सरकारी क्षेत्र में अनेक रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। निजी क्षेत्र में योग की संभावनायें बढ़ रही हैं। आज योग एक विशाल उद्यम का रूप ले चुका है। एक ओर योग प्रशिक्षण केन्द्रों में रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न हो रहे हैं तो दूसरी ओर योग के लिए आवश्यक सामग्री का उत्पादन करने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों भी योग में नये रोजगार के अवसर सृजित कर रही हैं। विदेशों में भारतीय योग प्रशिक्षकों की भारी माँग है तथा भारतीय युवक योग के माध्यम से विदेशों में आकर्षक वेतन और ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार देश में भी योग प्रशिक्षकों की भारी माँग होने के कारण रोजगार/स्वरोजगार के अनेक अवसर सृजित हो रहे हैं। इस प्रकार योग एक पूर्णतः रोजगारोन्मुखी एवं उद्यमिता मूलक पाठ्यक्रम है। इस अध्ययनशाला से योग शिक्षित छात्र जहाँ भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् (ICCR), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार जैसी अनेक संस्थाओं के माध्यम से विदेश स्थित भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों में योग शिक्षण एवं प्रचार प्रसार कार्य करके विश्वविद्यालय, प्रदेश एवं देश की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं, वही दूसरी ओर स्वरोजगार एवं उद्यमिता के रूप में योग प्रशिक्षण प्रदान कर प्रति माह रु.50,000/- (पचास हजार रु.) से अधिक आय अर्जित कर रहे हैं। इस प्रकार योग एक पूर्णतः रोजगारोन्मुखी एवं उद्यमिता मूलक पाठ्यक्रम है।

III - अध्ययनशाला— स्वामी विवेकानन्द स्मृति तुलनात्मक धर्म, दर्शन एवं योग अध्ययनशाला की स्थापना 1985 में हुई। उस समय अध्ययनशाला का नाम तुलनात्मक धर्म एवं दर्शनशास्त्र अध्ययनशाला था। सन् 2001 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत परियोजना के फलस्वरूप योग का डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम योग केन्द्र की स्थापना के साथ प्रारम्भ हुआ। 2007 में योग में एम.ए. का पाठ्यक्रम प्रारम्भ होने के साथ अध्ययनशाला का नाम “दर्शन एवं योग अध्ययनशाला”

-07-

रखा गया जो क्रमशः वृद्धिमान होते हुए आज वर्तमान नाम से पूर्ण विकसित विभाग का रूप ग्रहण कर चुका है।

इस अध्ययनशाला द्वारा प्रस्तावित स्वामी विवेकानन्द शोध पीठ के प्रस्ताव को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रु.85,00,000/—(पचासी लाख रुपये) के साथ स्वीकृति प्रदान की है। यह अध्ययनशाला एवं विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है क्योंकि पूरे देश में जिन 5 संस्थाओं के लिए यह पीठ स्वीकृत है उनमें यह अध्ययनशाला/विश्वविद्यालय भी एक है।

वर्तमान समय में इस अध्ययनशाला में निम्नलिखित पाठ्यक्रम सफलता पूर्वक संचालित हैं -

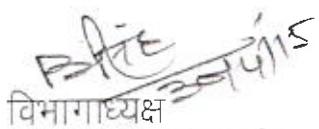
1. योग एवं अनुप्रयुक्त दर्शनशास्त्र में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (M.A.degree course)
2. दर्शनशास्त्र में स्नातकोत्तर (M.A.degree course)
3. पी.जी. डिप्लोमा इन योग एजुकेशन एण्ड फिलॉसफी (P.G.Diploma)
4. योग शिक्षा एवं दर्शनशास्त्र में प्रमाण-पत्र (Certificate Course)
5. तुलनात्मक धर्म एवं दर्शनशास्त्र में एम.फिल. (M.Phil. degree course)
6. दर्शनशास्त्र एवं योग में पी-एच.डी.

योग के उक्त पाठ्यक्रमों का संचालन वर्तमान में योग के वैशिष्ट्य वाले स्थाई पद के बिना, मात्र अतिथि व्याख्याताओं के माध्यम से, किया जा रहा है। योग केन्द्र की स्थापना के समय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली ने दो योग अनुदेशकों के पदों की स्वीकृति मानदेय सहित प्रदान किया था। किन्हीं कारणों से इन पदों की वचनवद्धता शासन से प्राप्त नहीं हो सकी (परिशिष्ट - 01)। योग की समकालीन वैश्विक स्वीकृति एवं माँग के परिप्रेक्ष्य में इस अध्ययनशाला में योग पाठ्यक्रमों के सुचारु संचालन के लिए योग से सम्बन्धित अधोलिखित पदों की स्वीकृति प्रस्तावित एवं निवेदित है—

IV - वार्षिक आवर्ती व्यय :

क्रमांक	पदनाम	पदसंख्या	वेतन	अनुमानित आवर्ती व्यय (प्रतिवर्ष)
1.	असिस्टेंट प्रोफेसर	01	बेसिक 15600-39100+ AGP-6000/-	5,53,620 / -
2.	योग अनुदेशक (पुरुष)	01	बेसिक 5200-20200+ GP-2800/-	2,07,120 / -
3.	योग अनुदेशक (महिला)	01	बेसिक 5200-20200+ GP-2800/-	2,07,120 / -
4.	योग सहायक	01	बेसिक 4750-7440+ GP-1300/-	1,58,700 / -
	कुल पद संख्या	04	छठवें वेतन आयोग के अनुसार	11,26,560 / - (प्रतिवर्ष)


विभागाध्यक्ष

Dr. Bhagwant Singh

(हस्ताक्षर एवं मुहर) & Yoga
P. S. S. University, Raipur-492010 (C.G.)


कूलसचिव

Registrar

P. S. S. University, Raipur-492010 (C.G.)
RAIPUR (C.G.)

परिशिष्ट - 01

- 09 -

(25)



No F 15-13/99(PES)

The Registrar,
Pt. Ravishankar Shukla University,
Raipur (M.P.)

तार : युनिग्रान्ट्स
Grants UNIGRANTS
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफर मार्ग
नई दिल्ली - 110002
UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADURSHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI - 110002

30 AUG 2000

SUB Promotion of Yoga Education & Practice in the universities - regd

Sr,

With reference to your letter no 1058/G-411/RISU dated 7-7-2000 on the subject cited above, I am directed to say that the Commission has agreed to the proposal of your university for establishment of Yoga Centre in the university and recommended the financial assistance of Rs. 1,00,000/- for initial furnishing, equipment & contingency (one time grant) & Two Instructors for the centre. The honorarium to Instructors for A and B class cities will be paid @ Rs. 7,500/- p.m. each and for remaining places @ Rs. 6,500/- p.m. each by the Commission.

It would be mandatory for the university to maintain the centre after the expiry of IX plan period on 31st March, 2002

The Commission has recommended the following guidelines for appointment of Yoga Instructors priority-wise -

1. Post-graduate (full time course) in Yoga/Yogic Science/Yoga Therapy/Yoga Studies etc from universities
2. Post-graduate Diploma (full time one year course) in Yoga/Yogic Science/Yoga Therapy/Yoga Studies etc from universities
3. Post-graduate Diploma (full time course) in Yoga/Yogic Science/Yoga Therapy/Yoga Studies etc from universities.

The university may appoint Two Yoga Instructors and send the attested photocopy of agreement with a yoga institution on a stamp paper and the joining reports alongwith the bio-data of Instructors to the Commission for further necessary action by the Commission.

Admissible on account grant is being sanctioned separately

Yours faithfully,

Sd/-
(Dr. R.K. Chauhan)
Joint Secretary

Copy to :-

Dr. Bhagwant Singh,
(In-charge Yoga Centre)
H.O.D. Comp. Rel. & Philosophy,
Pt. Ravishankar Shukla University,
Raipur (M.P.)

Sd/-
(Mrs. Shashi Munjal)
Section Officer

26

NOTICE

No.F.6-1/2014(NFE)

June, 2015

Subject:- XII Plan guidelines of the scheme of Epoch Making Social Thinkers of India.

XII Plan guidelines of the scheme of Epoch Making Social Thinkers of India are placed at Annexure-I, which are effective w.e.f. 22/12/2014.



**(Dr. Dev Swarup)
Joint Secretary**



27

ANNEXURE-I

**XII PLAN GUIDELINES FOR THE SCHEME OF
EPOCH MAKING SOCIAL THINKERS OF INDIA**

(2012 - 2017)

**UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADUR SHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI – 110002**

Website: www.ugc.ac.in

INDEX

Sl.No.	Item	Page No.
1.	Objectives	1
2.	Proposals	1
3.	Eligibility	2
4.	Operational Features	2
5.	UGC Assistance	3
6.	Disbursement	5
7.	Advisory Committee	5
8.	Review and Evaluation	5
9.	Format for Submission of Proposal	- Annexure-I 6
10.	Utilization Certificate	- Annexure-II 9
11.	Statement of Income and Expenditure	- Annexure-III 10

**XII PLAN GUIDELINES FOR THE SCHEME OF
EPOCH MAKING SOCIALTHINKERS OF INDIA**

1. Objectives

India has produced great thinkers and social leaders who, by their revolutionary and path breaking thoughts and actions, have left a lasting impact not only on India, but the world as a whole. They have developed indigenous ideas and have provided cultural and ethical identity to India. There is a great need to acquaint the teachers and students with their thinking and work and to involve them in studies, research and field work based extension service programmes of constructive work.

The Indian University system owes to the nation to conduct studies, research and extension programmes, which are pertinent and apply their ideas in the reconstruction of society on moral, ethical and spiritual foundations necessary for a non-violent social order.

Buddha emphasized on the age old concepts of compassion and ahimsa and tried to apply them for the formation of an egalitarian society. Gandhi gave a social dimension to the concept of peace and non-violence and demonstrated, both through his life and work, how it could be used as an instrument for fighting injustice at all levels. Nehru stood for the application of non-violence for resolving conflicts at the national, and more so at the international level, as well as modernization of society with emphasis on science and rationality. Ambedkar stressed on the empowerment of the oppressed as a means of their release from exploitation and injustice.

The ideas of these thinkers have an interrelated framework mutually supportive to each other and provide insights into the socio-economic and heartening to note that the performance of these centres in disseminating the ideas of these thinkers, has been satisfactory. In line of the interrelated framework of the ideas of these thinkers the UGC started the scheme of the Epoch Making Social Thinkers of India all sanctioned and encouraged the various centres in the universities / colleges during the XI plan period.

2. Proposals

The UGC extends financial assistance under this scheme to the university system for pursuing studies related to the thoughts and programmes of these great leaders. The assistance to the universities is on the basis of selection among the applications for the establishment and the work of the Centres of Buddhist, Gandhian, Nehru and Ambedkar studies with the above mentioned objectives. The programme of Buddhist Studies is funded wherever there is facility for learning the 'PALI' and/or SANSKRIT LANGUAGE. Where there is no such facility, it can be attached to another appropriate department such as History, Philosophy, Sociology and Ancient Indian Culture. In the examination of the proposal, the prior work of the department in the respective areas will be taken into consideration. Proposals with innovative ideas will be given considerable weightage.

- c. Conduct a full-time or part-time course of about 3 to 6 months, or of similar duration, for a group of teachers/students of the university, functionaries of nongovernment organizations, corporate executives and government officers, focusing on particular aspects of thinking and work of these social thinkers.
- d. Provide teaching support to other university departments by introducing or assisting in existing courses/papers on such studies indicated in different subjects of the department.
- e. Organize seminars/lecture series on some identified topics on such studies. The proposal for holding a National or International Seminar upto Rs.1 lakh, the centre can go ahead and more than Rs.1 lakh the seminar proposal must be printed and referred to the UGC. Lecture series may be organized in the Centre or in any other suitable place and material of these lectures may be placed in the library/university/college website for the use of the teachers, students and other interested persons.
- f. Conduct research/studies in the thoughts and programmes of the above mentioned thinkers.
- g. Conduct field work and action programmes on the basis of constructive programme related to the thoughts of the respective thinkers.
- h. Understand and disseminate the concepts relating to Buddha, Gandhi, Nehru and Ambedkar and the philosophies enunciated by them, related to social justice and equity, conflict resolution, non-violence and non-violent protest-movement, empowerment of women, rural development and related topics.
- i. Prepare modules of courses for short duration in the universities, established in the name of the respective thinkers, for the orientation of students, teachers and non-teaching staff.

Keeping in view that there is a need to re-orientate the above scheme, the literature being produced at the Centres need to be integrated with the teaching.

5. UGC Assistance

The following UGC assistance is provided for each of these studies for research and extension programmes:-

I	<u>Non Recurring</u>	
(i)	Equipment (audio-visual aids, computer etc.) (once at the time of the establishment of the centre.)	Rs.3,00,000/-
	Total	Rs.3,00,000/-
(II)	<u>Recurring</u>	
(i)	Books & Journals,	Rs. 50,000/-

- 2 One Subject Expert (External) (from the institute other than the Institute where the project is undertaken)
- 3 One nominee of the Vice-Chancellor/Head of Institution/Principal (in case of college)
- 4 Principal Investigator

The University/College should inform the UGC in the prescribed proforma certifying that all norms have been followed while selecting the Project fellow.

The fellowship entitlement will be effective from the date of implementation of XII Plan guidelines. Further, no claim of the fellowship for the period earlier than the date of implementation of the XII Plan guidelines of the scheme will be entertained.

The over and above Expenditure under the Head 'Hiring Services (one Project Fellow)', beyond Rs.2,50,000/- would be reimbursed on receipt of audited Utilization Certificate/Statement of actual Expenditure from the Universities/Colleges.

6. Disbursement

The UGC assistance will be disbursed to the universities / colleges. The grant can be claimed from the UGC for all non-recurring items in one installment as soon as the university / college is able to provide adequate space to the Centre. For recurring items, "on account" grant of 90% of the annual recurring grant will be given as first installment. The final 10% will be released when the audited accounts and Utilization Certificates & report of activities of the centre for the year. are submitted to the UGC.

After XII Plan, the disbursement of funds for setting up Study Centres may be included as part of Block Grants to Universities.

7. Advisory Committee

Each Centre is required to have an Advisory Committee with the Vice-Chancellor /Principal or his/her nominee in the Chair with the following membership:

- i. Three Professors nominated by the Vice-Chancellor / Principal / Director.
- ii. Two outside Experts in consultation with the Centre.
- iii. One expert to be nominated by UGC.

The Advisory Committee will meet twice a year to review the work. undertaken by the centre and recommend suggestions. appropriate programmes for further strengthening of the Centre.

8. Review and Evaluation

The proceedings of the Advisory Committee. along with the action taken on their recommendations, have to be furnished to the UGC annually, as also an annual report and accounts. The UGC Expert Committee will hold meeting once in the Plan period with the Heads of the centres to review the progress and plan for future action. The UGC assistance can be terminated if the functioning of the Centre is found to be unsatisfactory.

ANNEXURE -I

FORMAT FOR SUBMISSION OF PROPOSAL UNDER THE SCHEME 'EPOCH MAKING SOCIAL THINKERS OF INDIA'

I. UNIVERSITY / COLLEGE PROFILE

1.1 Name of the University/College : _____

1.2 Address : _____

1.3 State : _____

1.4 Date of Establishment : _____

1.5 Name of the Vice-Chancellor : _____

1.6 Name of the Registrar : _____

1.7 Type of the University : _____

1.8 Number of Colleges, if affiliating type : _____

1.9 Name of the university to which the college is affiliated (in case of college) : _____

1.10 Status of the university/college (Govt. aided/Private Govt. aided and covered under section 2(f) & 12B of the UGC Act, 1956)* : _____

1.11 Any other information : _____

Faculty	Departments
a) _____	_____
b) _____	_____
c) _____	_____
d) _____	_____

1.12 Mission defined by the University : _____

*A certificate from the State/Central Govt. to the effect that the university/college is Govt. aided/Private Govt. aided, may be enclosed with the proposal.

5. Director (University to submit three names of Professors/Senior Readers with their C.V.S)

5.1 Capacity to generate resources _____

5.2 Likelihood of State Government's approval to the Centre /Programmes and taking over the liability of the staff in the next Plan period.

5.3 Financial Assistance required _____

6. Any other details (Please specify) _____

Place : _____

Name and Signature
of Vice-Chancellor

Date : _____

(Please attach separate sheets if the space provided is insufficient)

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

UTILISATION CERTIFICATE

Certified that an amount of Rs. _____ (Rs. _____
 _____)
 against the grant of Rs. _____ (Rs. _____
 _____)
 sanctioned to _____ by the University
 Grants Commission vide its letter No. _____ dated _____
 towards _____
 has been utilized for the purpose for which it was sanctioned and in accordance
 with the terms and conditions as laid down by the Commission.

It is further certified that inventories of permanent or semi-permanent assets created/acquired wholly or mainly out of the grants given by the University Grants Commission as indicated above are being maintained in the prescribed form and are being kept up-to date and these assets have not been disposed of, encumbered or utilized for any other purpose.

If, as a result of check or audit objection, some irregularity is noticed at a later stage, action will be taken to refund or regularize the objected amount.

Registrar /Principal
 (with his seal)

(Signature of Chartered Accountant/
 Government Auditor with his seal)

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
STATEMENT OF INCOME & EXPENDITURE

Audited statement of income & expenditure in respect of _____

approved by the UGC vide letter No. _____ dated _____

Income		Expenditure (Head-wise & Item-wise)
1. Grants from UGC	: _____	1. _____
2. Interest earned by the university/college on UGC grant	: _____	2. _____
3. Others, if any	: _____	3. _____
		4. _____
		5. _____
		6. _____
Total	: _____	Total : _____

Registrar /Principal
(with his seal)

F.A./F.O.

(Signature of Chartered Accountant/
Government Auditor with his seal)

Note:- Statements of recurring and Non-recurring expenditure are to be sent separately.
Details of appointment of Project Fellow may also be furnished.



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

**GUIDELINES
FOR e-CONTENT DEVELOPMENT OF
PROJECT,
SUBMISSION FOR ASSISTANCE
FROM UGC
UNDER NME-ICT**

**University Grants Commission
Bahadur Sha Zafar Marg,
NEW DELHI – 110 002**

INDEX

S.N.	Topics	Page
1	Preamble	3
2	Who can submit proposals for e-content development	4
3	Responsibilities of the Host Institute.	4
4	Procedure for evaluation of proposals	4
5	Undertaking by project investigator (P I)	5
6	Principal investigator & co-investigator(s) and the implementing institution(s)	5
7	Project staff(s)	6
8	Sanction of pilot project/ detailed project	7
9	Funding and duration of pilot projects	7
10	Content development	7
11	e-content module & content duration	8
12	Project management and monitoring committee:	8
13	Delivery of product	8
14	Meta-Data and creation of information bank	8
15	Quality control	9
16	IPR & copyrights	9
17	Additional guidelines for release of grants in yearly installment and financial management	9
18	Additional set of criteria for monitoring the progress of the scheme	10
19	Proforma for submitting utilization certificate and progress report	10
20	Incentives for creation of e-content programme	10
	Annexure – I	11
	Annexure – II	12

“e-PG Pathshala”

A Project under National Mission on Education through ICT (NME-ICT)

1. PREAMBLE

The National Mission on Education through Information and Communication Technology (NME-ICT) is envisaged as a Centrally Sponsored Scheme to leverage the potential of ICT, in teaching and learning process for the benefit of all the learners in Higher Education Institutions at any time any where mode. Its motto being “to provide connectivity up to the last mile”, the NME-ICT aims to extend computer infrastructure and connectivity to over 32000 colleges existing at present and each of the departments of over existing 550 universities/deemed universities and institutions of national importance in the country. The numbers of institutions/Departments are is grow in future.

NME-ICT seeks to bridge the digital divide, i.e., the gap in the skills to use computing devices for the purpose of teaching and learning among urban and rural teachers/learners in higher education domain and empower those, who have hitherto remained untouched by the digital revolution and have not been able to join the mainstream of the knowledge economy. This will enable them to make best use of ICT framework for teaching and learning.

NME-ICT is focused primarily on development of high quality e-content in all disciplines and subjects at various levels. The projects under NME-ICT can broadly be classified as:

(a) e-Content Development (b) Infrastructure Development (c) Social Impact

The topics covered under each domain are not exhaustive but indicative.

a) e-Content Development (including all four quadrants)

- ICT Methodology for Teaching and Evaluation
- Modules Preparation
- Workshops for Training

e-PG Pathshala: The MHRD, under its National Mission on Education through ICT, has Sanction vide communication No. F.B-13/2011-TEL dated 29th September 2011, Grant in Aid to UGC for production of e-content in 77 subjects at postgraduate level. The content and its quality being the key component of education system, it is proposed to create high quality, curriculum-based, interactive content in different subject across all disciplines of social sciences, arts, fine arts & humanities, natural & mathematical sciences and linguistics and languages. E-content, so developed would be available in open access through a dedicated Learning Management System as well as through Sakshat Portal.

Standing Committee, e-PG Pathshala, UGC: The UGC has constituted a Standing Committee, e-PG Pathshala, on e-content creation to monitor and coordinate the activity of content creation in a most effective and efficient manner. In order to have uniformity of the UGC e-Content project visa viz the e-content being developed under NMEICT, MHRD, the SC UGC has been expanded to include 13 regular Standing Committee Members of the NMEICT, MHRD. The Standing Committee is the apex level decision making body for the e-PG Pathshala, at present, under the

Chairmanship of Prof. M. Anandkrishnan. The Dy. Secretary, UGC is the Coordinator of the Standing Committee, e-PG Pathshala, UGC.

2. WHO CAN SUBMIT PROPOSALS FOR e-CONTENT DEVELOPMENT?

“e-content development” is an entirely new project initiated by MHRD/UGC, it is quite possible that the PIs/Co-PIs may not have prior experience in the field similar to that of the audio-visual programmes. Proposals for e-Content development under e-PG Pathshala by a PI or PI & Co-PI(s) may be submitted, through the Host Institute under which the PI(s) are working, as per prescribed “Proforma for submitting a Project proposal” for a subject. The proposals may be submitted to the Chairman, University Grants Commission, New Delhi by any of the following:

- (a) Any PG teacher, engaged in teaching in an Institution recognised by the UGC, for at least ten years, in the particular discipline.
- (b) Any educational institutions in the country imparting higher education, who agree with the aims and objectives of the NME-ICT/UGC, shall be eligible to submit proposals.
- (c) An Agency/Institution/Individual through invitation of the NME-ICT/UGC.

3. RESPONSIBILITIES OF THE HOST INSTITUTE.

The Host Institute, where the PI(s) is/are working may forward an application of PI(s) for e-Content development under e-PG Pathshala by a PI or PI & Co-PI(s) in accordance with the ‘Guidelines for e-content development’ and ‘Proforma for submitting a Project proposal’ for seeking financial assistance from UGC, under e-PG Pathshala, NME-ICT programme for development of e-content of a subject/course.

The Standing Committee, e-PG Pathshala, UGC having reviewed the application in prescribed format and forwarded by the Host Institute, shall call the PI and /or PI & Co-PI(s) to present their proposal before it. The Standing Committee, e-PG Pathshala, UGC, may offer its comments for modifications of the proposal, if any and approve the proposal.

The funds on this shall be transferred by the UGC to the Host Institute. In order to ensure that a number of projects sanctioned to PIs working at different Host Institutes are developed uniformly and in according with the Guidelines and Norms set by the Standing Committee, e-PG Pathshala, UGC, it is important that common set of understanding is arrived between UGC, all the PI(s) and the Host Institute. Accordingly a uniform Memorandum of Understanding shall be signed between the UGC, all the PI(s) and the Host Institutes individually.

4. PROCEDURE FOR EVALUATION OF PROPOSALS

The procedure for evaluation of the proposals would be more or less the same as adopted by funding agencies like UGC, DST except the benchmarks for judging the project would be suitably modified in view of above mentioned issues.

Proposals can be submitted online on **e-PG Pathshala** website. Each Standing Committee, e-PG Pathshala, UGC member gets an opportunity to go through the Project and review the proposal.

All the projects sanctioned under e-PG Pathshala, shall have an expert group for monitoring projects called **Project Review and Supervisory Group (PRSG)**. The PI is required to submit names of 10 Subject Experts to the UGC and the Standing Committee, e-PG Pathshala, UGC Constituted by the UGC shall choose few or add some more experts to form a PRSG for each Subject. These expert groups identified for sanctioned projects shall monitor the progress the progress periodically and submit the report to the SC, UGC.

5. UNDERTAKING BY PROJECT INVESTIGATOR (PI)

While submitting fresh proposals, the PIs on behalf of Implementing Institution has to submit an undertaking to the SC UGC, that the proposal being submitted by them has not been submitted elsewhere, nor is it a repetition of any other project for which they have received funding from any other agency. However, if they want to submit the same or similar proposal to any other funding agency, they should inform SC UGC.

6. PRINCIPAL INVESTIGATOR & CO-INVESTIGATOR(S) AND THE IMPLEMENTING INSTITUTION(S)

- I. The Principal Investigator (PI) has the primarily responsibility for the implementation of the project. The project team consists of the PI, Co-Investigator(s) (upto two) and the project personnel appointed as per the sanction order, if any. It is necessary to ensure that the project is carried out by the project team in a cohesive manner. Periodic meetings of the PRSG are essential for this purpose.
- II. In case of PIs who would be superannuating during the duration of the project, association of a "in service" Co-Investigator may be ensured by the Institute authorities. In such cases, the Institute authorities should inform to the SC UGC, well in advance, about their "no objection" for providing the infrastructural facilities to the PI for implementation of the project after his superannuation.
- III. Having accepted the responsibility for the implementation of the project, the PI should be committed to implement the project over its duration and should have no plans to go on long leave.
- IV. PI may engage Teachers with ten years of teaching PG experience who are in service or retired, as content writers.
- V. In case, the PI is shifting to another institution on new appointment/ transfer/ long term deputation, the project could be transferred to that institution with the mutual consent of both the institutions and of the SC UGC. Such requests for transfer of the project should be sent well in advance and should be accompanied with 'No Objection' certificates from both the institutions and the Endorsement Certificate from the new Institution.
- VI. In case the PI leaves the project due to unforeseen circumstances, the Co-Investigator could be considered as the PI, subject to the approval of Head of the Institute and the SC

UGC. Such a request should be sent at least 4-6 months in advance along with a detailed bio-data of the Co-Investigator.

- VII. The PI as well as the implementing institution has the responsibility of informing the SC UGC about any change in the status of the PI/ Co-Investigator including relieving them on short term deputation for a continuous period of 3 months or more.
- VIII. The project stands terminated in the absence of the PI/ Co-Investigator for a continuous period of 3 months without intimation to the SC UGC.
- IX. The implementing institution has an important role to play and in consultation with the SC UGC take steps to ensure successful completion of the project, before relieving the PI.
- X. The implementing Institute should provide full infrastructural facilities such as accommodation, water, electricity, and communication facilities etc. for smooth implementation of the project.
- XI. Payment towards Project overhead charges to Implementing institute is not admissible.

7. PROJECT STAFF(S) & HONORARIUM TO PI(s)

- i. All personnel including Research personnel appointed under the project, for full/ part time duration of the project, are to be treated as temporary employees and will be governed by the Administrative rules/ service conditions of the implementing Institute. No reference on these issues be made to this UGC. The UGC will have no liability, whatsoever, for the project staff after completion of the project duration.
- ii. Scale and emoluments for the posts not covered under this order are governed by norms prevalent in the implementing Institution or as may be decided by this Department.
- iii. The total emoluments spent (i) on engaging personal (ii) towards the work outsourced (iii) payment of honorarium to regular staff and (iv) on procurement of Hardware and / or Software required for development of e-content should not exceed the budget allocated for the project.
- iv. Honorarium, to PI(s) if any, shall be payable only after completion of the project and acceptance of deliverables by the Government of India, Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development. The Honorarium shall be regulated strictly as per rules and regulations in force from time to time which, inter alia includes provision of SR- 12 and within the prescribed ceilings.
- v. Further the Honorarium to PI(s) in no case shall exceed 10% of the cost of the project and no one individual would get more than 20% of his/her annual Salary as honorarium for the whole year including honorarium received from any other source whatsoever.

8. SANCTION OF PILOT PROJECT/ DETAILED PROJECT

- a) Every PI/ co-PI is required to give a presentation before the Standing Committee, e-PG Pathshala. In view of fairly wide range of available domain expertise among SC members

as well as in the areas of teaching methodology, content development and other aspects of education. However, if the Standing Committee, e-PG Pathshala, UGC feels that expertise in certain areas is not available, the committee may associate some external experts.

- b) Based on presentation and critical examination of the proposal the Standing Committee, e-PG Pathshala, UGC shall either recommend sanction of the project or may makes suggestions for further improvement. The maximum duration of completing a Pilot project would be one year or as approved by SC UGC.
- c) It is decided to adopt two-step approach of considering a pilot process and then request a comprehensive evaluation of the full proposal within a few months to sanction the full project by the time the pilot project can be reviewed and assessed as successful by PRSG (domain experts).
- d) On completion of pilot project, the SC would invite some external experts or follow the PRSG recommendation on review of the project. Based on the feedback of the experts, the SC would invite PI for presentation for the detailed project.

9. FUNDING AND DURATION OF PILOT PROJECTS

Rule for funding of the Pilot project (under the category of content development) is restricted to Rs.7.00 Lakhs or 10% of the total cost of detailed project, whichever is more.

The funding guidelines to be followed by SC are advisory in nature. However, in special cases the SC may use its discretion to deviate from these guidelines with justification.

These guidelines may be reviewed from time to time by the UGC, so that mission objectives can be achieved.

Note: These guidelines are within the framework of NME-ICT. In case of any conflict with NME-ICT guidelines, Mission guidelines will prevail.

10. CONTENT DEVELOPEMENT

E-Content Development consists of (i) Academic content writing and (ii) e-Content production. The Academic content may be written by the Subject Experts. However, the services of INFLIBNET and CEC including its EMMRCs spread across the country or Production Houses, having experience in production of e-Content and Video programmes, especially for education may be sought by the Implementing Institution. Proposals for e-Content development may be submitted keeping in mind that the product is developed and delivered to SC UGC in an integrated form, following Guidelines with regard to Template and Technical parameters:

However, if it is found that the quality of e-Content is not as per Technical and Production Guidelines, the Implementing Institution / individual assigned to produce the e-Content shall have to get it corrected within budget sanctioned to the PI.

11. e-CONTENT MODULE & CONTENT DURATION

Content duration has been estimated on the basis of the number of hours that are required to transact the content in the classroom. For example, a course in the classroom requires one credit and a credit is equivalent to 15 hours classroom teaching. The content of a course will be taken as 15 hours. On an average, UG students have to take 6 to 8 papers in an academic year. Therefore, during the study period of 3 years a student may take 18 - 24 papers. A paper shall comprise of 40 modules each module of one hour duration and to include production in 'Four Quadrants' as per Annexure- I.

12. PROJECT MANAGEMENT AND MONITORING COMMITTEE:

An Academic Content Advisory Committee shall be constituted by the Implementing Agency, i.e., UGC, comprising of a panel of Subject Experts, Technical Experts and Media professionals, Managers to monitor and review the progress of implementation of the e-Content Scheme assigned to the Instituted / Agency.

The committee shall be responsible for selecting and engaging (i) a Course Coordinator for each of the e-Course assigned and (ii) Production House/Agency for production of e-content Development. The Academic Content Advisory Committee shall meet once in three months, or more often if needed, to review the quality of Academic Content delivered by the Subject Experts and quality of Production delivered by the Production Agency/ Implementing Agency of each e-Content course and recommend the corrections, changes etc that are required in accordance with the Guidelines on this issued.

The NME-ICT Mission document will prevail all issues over this document in case of any conflicts and contradictions.

13. DELIVERY OF PRODUCT

The Programme Production Agency shall take the Academic content from the Subject Coordinator/ Subject Expert, engaged by the Implementing Agency and shall produce e-Content Module as per Academic and Technical criteria and provide Graphics, Animation and Multimedia inputs, wherever needed. The Programme Production Agency shall also incorporate necessary modifications as communicated by the Subject Coordinator or the Academic Content Advisory Committee.

14. META-DATA AND CREATION OF INFORMATION BANK

The e-content Development Project under NME-ICT envisages development of a large number of e-modules, video programmes, etc., related to a number of subjects of UG and PG and e-PG Pathshala. It is important that key words appearing in each module are recorded on a Production Detail Report (PDR format to be provided) by the Subject Expert/Production Agency. This information is then tagged with the e-Content and stays with it forever. A Computerized Library Management Software (CLMS) created to handle such information proves to be boon in churning out data out of an infinite number of programmes stored. Such Meta-data (data about the programmes) can be surfed by anybody on the net by pressing a keyword and the person can seek any of the information related to the programme, its synopsis, etc.

15. QUALITY CONTROL:

The content authenticity shall be the responsibility of the PI, however :

- (i) Technical quality,
- (ii) Subject/Academic Content,
- (iii) Editorial quality
- (iv) Pedagogical values etc

shall be the responsibility of the Production agency and should follow instructions on this laid down above. Further, issues concerning copyright aspects / intellectual property rights are to be taken care of by the e-Content production agency and PI.

The final products in the form of e-Content modules shall finally be previewed and approved by the Academic Content Advisory Committee before making it available to the public.

16. IPR & COPYRIGHTS

The intellectual Property Rights (IPR) and Production Copy Rights of the e-Content and other products developed shall rest with the NME-ICT, however the Subject Expert delivering the lecture(s), text, diagram's, Chart(s) etc shall submit an undertaking in writing to the SC UGC that he/she has not violate the Copyright issues on this.

17. ADDITIONAL GUIDELINES FOR RELEASE OF GRANTS IN YEARLY INSTALMENT AND FINANCIAL MANAGEMENT

- i. The grants for the project shall be released on the basis of yearly requirements taking note of the progress and expenditure incurred. The first sanction order indicates the budgetary allocation for the duration of the project under various heads like Equipment, Manpower, Travel, Consumable, Contingency etc. In specific cases, the item, apart from these heads, for which an allocation is made, will be indicated separately.
- ii. The first installment of grant shall be released along with the first sanction order.
- iii. Diversion of funds from non-recurring head i.e., Equipment to Recurring head like Manpower, Consumable etc. is normally not allowed. However, reallocation/ re-appropriation of grants under different heads require prior approval of SC UGC.
- vi. All the assets acquired from the grant will be the property of Government of India and should not be disposed off or encumbered or utilised for purpose other than those for which the grant had been sanctioned, without the prior sanction of The NME-ICT Secretariat.
- vii. After completion/ termination of the project, the NME-ICT will be free to sell or otherwise dispose off the assets, which are the property of the Government. The Institute shall render to the Government necessary facilities for arranging the sale of these assets. The NME-ICT also has the discretion to gift the assets to the Institute or transfer them to any other Institute if it is considered appropriate and justified.
- viii. The SC UGC reserves the right to terminate the project at any stage if it is convinced that the grant has not been properly utilised or appropriate progress is not being made.

18. ADDITIONAL SET OF CRITERIA FOR MONITORING THE PROGRESS OF THE SCHEME:

The proposals will be evaluated by the Academic Content Advisory Committee, keeping in mind the following criteria:

- a. Technologically Friendly: so as to be downloaded and used on any computer either independently or in a LAN situation;
- b. Learner Friendly: for easy navigation;
- c. Learner Centric: to be useful in self-instructional mode;
- d. Teacher Friendly: so as to be used in various teaching-learning methods such as classroom lectures, tutoring to a group, lab session, etc.;
- e. Employing Learner Centric Pedagogy: specifically, the designer of the e-Content should pay attention to the teaching model used - such as simple information communication, exploratory approach, discovery approach, mastery learning etc. Many types of interactive methods should be included to make the learning process effective and efficient.
- f. Self-evaluative: so as to have plenty of evaluation material to give feedback to the learner as to his/her achievements in a given topic of the course and including formative as well as summative evaluation.
- g. Object Based Learning/Teaching: so as to state specifically the objects of learning/teaching and employ different strategies for skill, competency and functionality developments.

19. PROFORMA FOR SUBMITTING UTILIZATION CERTIFICATE AND PROGRESS REPORT:

Statement of Expenditure and Utilisation Certificate (**Annexure-II**) shall be submitted to NME-ICT as per usual norms and procedures. It should also be uploaded on the Project Website linked to Sakshat.

20. INCENTIVES FOR CREATION OF e-CONTENT PROGRAMME

The teachers/subject experts who put their rich experience in the development of e-Content will be given due recognition by considering their work on development of ten e-content modules as equivalent to a publication of a paper in an International peer reviewed journal/Refereed Journals, subject to the condition that an appropriate notification in this regard is to be decided and issued by the MHRD/UGC.

Content Generation in 4 Quadrant

<p>2nd Quad e-Tutorial</p> <p>Video and Audio Content in an organised form, Animation, Simulations, Virtual Labs</p>	<p>1st Quad e-Content</p> <p>Textual Document, PDF / e-Books / illustration , video demonstrations / documents & Interactive simulations wherever required</p>
<p>3rd Quad Web Resources</p> <p>Related Links, Wikipedia Development of Course, Open Content on Internet, Case Studies, Anecdotal information, Historical development of the subject, Articles</p>	<p>4th Quad Self Assessment</p> <p>MCQ, Problems, Quizzes, Assignments & solutions, Online feedback through discussion forums & setting up the FAQ , Clarifications on general misconceptions</p>

UTILIZATION CERTIFICATE

(To be sent to the UGC)

..... College/University

Certified that the Project Grant of Rs. _____ (Rupees _____) approved by the SC UGC for e-Content Development Project at the College/University/Institution/Agency has been utilized as per details given below:

Amount of grant received from the UGC	:	
Details of expenditure incurred	:	
(a) Honorarium to the Content Developer/Subject Expert etc.	:	
(b) Secretarial Assistance	:	
(c) Travel Grant	:	
(d) Contingency/compilation and Communication Expenses	:	
(e) Equipment/Hardware/Devices	:	
(f) Miscellaneous	:	
(g) Total expenditure	:	
(h) Unspent balances refunded/refundable to the UGC:		
(i) Balance grant payable by the UGC		

Certified further that all the terms and conditions laid down in the SC/UGC letter no. _____ dated _____ have been fulfilled by the College/University/Agency and the grant has been utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Certified further that the inventories of permanent and semi permanent assets created/acquired wholly or mainly out of the grants given by the UGC as indicated above are being maintained in the prescribed form and are being kept up to date and these assets have not been disposed off, encumbered or utilized for any other purpose.

- Signature of the PI
- Signature of the Auditor/Chartered Accountant
- Signature of the nominated officer of the University/College/Institution/Agency authorized to operate the bank account jointly

विषय:—बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्र० मिसिल संख्या 15-1/2014 (राजभाषा) दिनांक 16 दिसंबर 2014 एवं क्र० मिसिल संख्या 15-1/2014 (राजभाषा) दिनांक 22 जून 2015 के द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय योजनांतर्गत हिन्दी विभाग की स्थापना के संबंध में भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है ।

विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर हिन्दी विभाग के लिए प्रोफेसर-01 पद, एसोसियेट प्रोफेसर-02 पद, असिस्टेंट प्रोफेसर-04 पद स्वीकृत किए गए हैं । भवन निर्माण हेतु रू० 1.00 करोड़, उपकरण हेतु रू० 5.00 लाख एवं आवर्ती व्यय के अंतर्गत प्रतिवर्ष पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाओं 50,000/-, गोष्ठी, सम्मेलन, कार्यशाला हेतु रू० 1.00 लाख, आकस्मिक व्यय हेतु 50,000/- कुल राशि रू० 1,07,00,000/- अनुदान स्वीकृत किया गया है उपरोक्त स्वीकृति के आधार पर राशि रू० 2.00 लाख प्राप्त हो चुके हैं ।

राज्य शासन को हिंदी विभाग की स्थापना एवं शैक्षणिक पदों की वचनबद्धता के संबंध में वि०वि० का पत्र क्र० 6879/स्था०/सा०प्रशा०/2014 रायपुर दिनांक 24/12/2014 भेजा गया है ।

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्र० F.No. 74-1/2015(SU-II) dated 5th June 2015 के द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय योजनांतर्गत स्वामी विवेकानंद चैयर स्थापित करने के संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है ।

इस स्वीकृति के आधार पर वि०वि० अनुदान आयोग ने राशि रू० 10.00 लाख का अनुदान भुगतान अलग से किए जाने की जानकारी दी है । प्रस्ताव के अनुसार बजट विवरण निम्नांकित है :-

(राशि 5 वर्षों के लिए)

1. Pay to the Chair Person 100000/- p.m.	60,00,000/-
2. Books & Journals 150000/-	1,50,000/-
3. Travel (Local & National) 1,00,000/- p.a.	5,00,000/-
4. Secretarial Assistance 1,50,000/- p.a.	7,50,000/-
5. Organization of Conf./Seminar etc. 1,00,000/- p.a.	5,00,000/-
6. Contingency towards hiring assistance for field work 6,00,000/- Data collection & analysis/ office expenses 1,20,000/- p.a.	

Total Rs.

85,00,000/-

3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्र० D.O.No. 1-2/2014(Sports/Policy) dated 5th June 2015 के द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय के लिए Scheme for development of Sports Infrastructure and Equipments योजना के अंतर्गत प्रेषित प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है ।

इस प्रस्ताव के अनुसार वि०वि० अनुदान आयोग ने 50 Bedded Sports Hostel के लिए राशि रू० 75.00 लाख का अनुदान स्वीकृत किया है ।

4. बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अनुदान हेतु प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को बनाकर प्रेषित किया गया था। पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव के अनुक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम बार प्रेषित पत्र क्रं० No. 1285/Grant Cell/2014 dated 15/09/2014, 1730/Grant Cell/2014 dated 19/11/2014, 1796/Grant Cell/2015 dated 13/01/2015, 1797/Grant Cell/2015 dated 13/01/2015, 1799/Grant Cell/2015 dated 13/01/2015 के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्रं० F.No. 74-1/2012(SU-II) dated 12th March 2015 के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की गई है। वि०वि० अनुदान आयोग के द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुसार विभिन्न मदों में बजट आवंटन निम्नानुसार है।

Sr. No.	Items	XII Plan Allocation as re-priorities (Rs. in lac)
01.	Construction and Renovation of buildings	600.00
02.	Campus development	50.00
03.	Staff	150.00
04.	Books & Journals	125.00
05.	Laboratory equipment and infrastructure	250.00
06.	Innovative Research Activities	100.00
07.	University industry	5.00
08.	Development of ICT	20.00
09.	Health Care	5.00
10.	Student amenities including hostels	50.00
11.	Travel grant	40.00
12.	Conf./Seminar/Symposium/Workshops	25.00
13.	Publication grant	5.00
14.	Appointment of Visiting Professor/Visiting fellows	10.00
15.	Establishment of career and Counseling cell	5.00
16.	Day care Centers	2.00
17.	Basic facilities for Women	10.00
18.	Faculty Development Program	20.00
	Total amount	1472.00

विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार निम्नानुसार उल्लेखित विभागों में शैक्षणिक पदों की स्वीकृति प्रदान की है :-

1. इन्वायरमेंटल साइंस 01 एसोसिएट प्रोफेसर, 03 असिस्टेंट प्रोफेसर
2. टूरिज्म मैनेजमेंट 01 असिस्टेंट प्रोफेसर
3. माइक्रोबायोलॉजी 01 असिस्टेंट प्रोफेसर
4. बायोकेमेस्ट्री 01 असिस्टेंट प्रोफेसर
5. अंग्रेजी 01 असिस्टेंट प्रोफेसर
6. गणित 01 असिस्टेंट प्रोफेसर (Cryptography)
7. भौतिकी 01 असिस्टेंट प्रोफेसर (Space Physics/Astronomy)

सया म,

16 DEC 2014

कुलसचिव
पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर-492010 (छत्तीसगढ़)

विषय: 12वीं योजना के अंतर्गत अनुदान प्राप्त केन्द्रीय/राज्य/मानित विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभाग की स्थापना करने हेतु अनुमोदन।

महोदय/महोदया

उपर्युक्त विषय से संबंधित आपका प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। समिति की अनुशंसा के आधार पर आयोग ने आपके विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग की स्थापना हेतु निम्न विवरण अनुसार स्वीकृति प्रदान की है:

क्र. सं.	मद	आयोग द्वारा स्वीकृत पद एवं राशि	
1.	प्रोफेसर	1	(वेतन नियमानुसार वास्तविक)
2.	ऐसोसियेट प्रोफेसर	2	
3.	असिस्टेंट प्रोफेसर	4	
4.	भवन निर्माण	₹ 1,00,00,000/-	
5.	उपकरण	₹ 5,00,000/-	
	आवृत्ति व्यय प्रतिवर्ष		
6.	पुस्तकें एवं पत्र, पत्रिकाएँ	₹ 50,000/-	
7.	गोष्ठी, सम्मेलन, कार्यशाला	₹ 1,00,000/-	
8.	आकारिमक व्यय	₹ 50,000/-	
	योग	₹ 1,07,00,000/-	

उपरोक्त सहायता इस अनुमोदन पत्र के जारी करने की तिथि से 31.03.2017 की अवधि तक मान्य होगी। उपर्युक्त अनुदान के लिये नियम व शर्तें वही हैं जिन्हें 12वीं योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालयों के विकास कार्यक्रमों को अनुदान दिए जाने के लिए निर्धारित किया गया है।

केन्द्रीय/राज्य/मानित विश्वविद्यालय, भवन निर्माण के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के दिशा निर्देश के अनुसार ही प्रस्ताव भेजें।

विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षण के लिए स्वीकृत पदों के सन्दर्भ में आयोग को आश्वासन/एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आयोग द्वारा अनुमोदित वित्तीय सहायता की अवधि की समाप्ति के पश्चात भी उक्त अनुमोदित पदों को राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा जारी रखा जाएगा। यह प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही अनुमोदित पदों के लिए आयोग द्वारा देय अनुदान जारी किया जाएगा।

ह वा अनुमादत पदा का नरस्त मान लया जाएगा।

स्वीकृत शैक्षणिक पदों की भर्ती/नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार की जाए और निम्नलिखित दस्तावेज आयोग को प्रेषित किए जाएं:

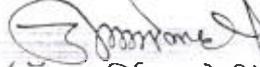
1. विज्ञापन की प्रतिलिपि
2. चयन समिति की अनुशंशा
- 3 चयनित उम्मीदवार का बायो डाटा
4. कार्यग्रहण सूचना
5. मूलवेतन और अन्य भत्ते आदि

अनुदान राशि जारी करने हेतु विश्वविद्यालय बैंक से सम्बन्धित निम्न विवरण शीघ्रताशीघ्र rajbhasha.ugc@gmail.com पर उपलब्ध कराए:

(क)	बैंक का नाम एवं शाखा का पता
(ख)	खाता संख्या
(ग)	खाते का स्वरूप- बचत/चालू/नकद साख
(घ)	आई.एफ.एस.सी. शाखा का कोड
(ङ)	एम.आई.सी.आर. शाखा का कोड
(च)	क्या बैंक खाता RTGS/NEFT सहायता प्राप्त है, RTGS/NEFT अथवा दोनों
(छ)	खाताधारी का नाम व पता

विश्वविद्यालय पत्र में दी गई शर्तों की मंजूरी के संदर्भ में कृपया अपनी स्वीकृति शीघ्र ही प्रेषित करें, जिसके आधार पर आयोग द्वारा अनुदान की देय राशि यथास्थिति निर्गत की जाएगी।

भवदीया,


(डॉ० उर्मिला देवी)
संयुक्त सचिव



UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADUR SHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI-110002

F.No. 74-1/2015(SU-II)

June, 2015

To,

The Registrar,
Pt. Ravishankar Shukla University,
Raipur - 492 010
Chhattisgarh.

5 JUN 2015

Subject: **Establishment of Swami Vivekananda Chair in Universities during XII Plan Period -reg.**

Sir,

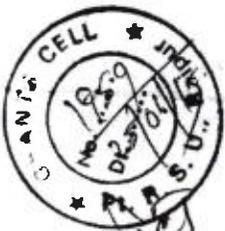
~~This is with reference to your letter No.1868/KS/2014 dated 29.10.2014~~ on the above subject. In this regard, I am directed to inform you that Expert Committee in its meeting held on 5th January, 2015 evaluated the proposals for Establishment of Swami Vivekananda Chair in Universities during XII Plan Period and recommended the proposal. Accordingly, UGC conveys its approval for establishment of Swami Vivekananda Chair at Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur for the remaining period of XII Plan Period.

The university may incur the expenditure strictly as per norms of the scheme and submit the statement of expenditure incurred (year-wise) towards the Chair along with audited utilization certificate, particulars of the persons appointed, period of appointment, salary statement (month-wise and year-wise) and details of the expenditure incurred under the head contingency, seminar/conference, travel and books & journals to enable UGC to take further necessary action in the matter.

However, an 'on account' grant of Rs.10.00 lakh is being released separately.

Yours faithfully,

(Ritu Oberoi)
Under Secretary



21/02/15
25/06/15
24/6/2015

369 /KT-524
24/06/15

0.715



कार्यालयीन टीप

1. सहायक फ़ैकल्टी के पेनल (Guidelines for Empanelment of Adjunct Faculty in Universities and College) के निर्धारण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त Guideline पर विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तीन नयी योजनाओं (1) Community College, (2) B.Voc. Degree Programme and Deen Dayal Upadhyay Koushal केन्द्र, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में प्रारंभ किया गया है। यह योजना छात्रों में Skill Development एवं आर्थिक उन्नयन के लिए लागू की गई है।

इस योजना के लिए वर्तमान में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में फ़ैकल्टी नहीं होने के कारण योजनाओं के क्रियान्वयन में परेशानी होगी। अतः यह महसूस किया जा रहा है कि विभिन्न उद्योगों, तकनीकी, वाणिज्य विषय आई.ए.एस., आई.पी.एस. एवं अन्य अभिरूचि रखने वाले अधिकारी से और शिक्षाविद् का एक पैनल तैयार कर उपरोक्त योजनाओं को क्रियान्वयन किया जाना उचित होगा। अतः विशेषज्ञों के रूप में उपरोक्त बुद्धिजीवियों का पैनल **Adjunct Faculty** बनाने पर विचारार्थ प्रस्तुत।

2 54

Guidelines for Empanelment of Adjunct Faculty in Universities and Colleges



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

**UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADUR SHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI**

Website : www.ugc.ac.in

Guidelines for Empanelment of Adjunct Faculty in Universities and Colleges

1. Preamble

The expectations from the higher education system have undergone a significant change over the last few years. The key thrust has been on improving the employability prospects of the graduates and also improving the quality and quantum of research. Therefore, it becomes imperative to involve experts, professionals and researches from diverse fields to contribute to the emerging needs of higher education system. The Indian higher education system is poised to make itself more relevant to the needs of industry and employment opportunities keeping in mind the rapid changes in job requirements and needs of the economy.

Taking an integrated initiative towards skill development and upgradation of the competencies, the Commission has recently launched three new schemes namely Community Colleges, B.Voc degree programme and Deen Dayal Upadhyay KAUSHAL Kendras. Universities and colleges offer courses from certificate up to postgraduate and research level degrees aimed at skill development and upgradation to meet the existing and emerging economic and industrial needs at the regional and national level under these scheme. The courses are offered with active involvement of industry partners in governance, curriculum development, delivery of courses and assessment of learners. Acute shortage of quality faculty is widely felt in the system of higher education as a whole. However, it is felt more prominently in skill based courses.

It is well realized that there is lot of creative talent and intellectual resources available within the country that are not formally connected to the higher education system. It is imperative that the expertise and experience of such individuals, who are outside the main stream academic system, flows into our universities. This would enhance, strengthen and improve the quality of teaching, training and research. The current massive expansion phase in higher education, mandating huge programmatic diversity, also requires that faculty resources be augmented by utilizing the services of superannuated academics, reputed scientists, engineers, physicians, advocates, artists, civil servants including skilled professionals, both serving and retired. It is also essential that such faculty is hired with the same degree of rigour as adopted for full-time faculty so that right type of candidates are identified for such assignments. It is also necessary to have uniformity and transparency in the process of hiring adjunct faculty in the institutions of higher education.

2. Objectives:

- 2.1. To develop a useful and viable collaboration between institutions and industry and enhancing quality of education and skills by involvement of academicians, scholars,

practitioners, policymakers and skilled professionals in teaching, training, research and related services on regular basis;

- 2.2. To attract distinguished individuals who have excelled in their field of specialization like science and technology, industry, commerce, social research, media, literature, fine arts, civil services and public life into the academic arena, to enrich the overall learning processes by bringing external perspectives to regular teaching. Such interactions are expected to foster trans-disciplinary approach and synergize the outside 'real world' experience with the inside intellectual pursuits in the university;
- 2.3. To promote the interaction of skilled professionals with the learners and facilitate the imparting of industry relevant standards in skills, acceptable nationally, which could fulfill the need for skilled workforce and also to undertake R&D in the areas related to skill education & development, entrepreneurship and employability *etc*;
- 2.4. To enable higher educational institutions to access the eminent teachers and researchers who have completed their formal association with the university/college, to participate in teaching, to collaborate and to stimulate research activities for quality research at M. Phil and Ph. D. levels; and to play mentoring and inspirational role;
- 2.5. To recognize the skills of professionals in their respective areas of excellence irrespective of their academic qualifications to impart training to the learners of skill based vocational courses in Universities and Colleges.

3. Target Groups:

Professionals, experts, officials and managers having experience of working in:

- 3.1. Teaching and research organizations supported by bodies like ICAR, ICSSR, CSIR, ICMR, DRDO, Central and State Universities, *etc*.
- 3.2. Central and state public sector undertakings (PSUs), business corporations, NGOs and professional associations.
- 3.3. Civil servants (IAS / IPS / officials from Central and Provincial Services) and professionals & officials from professional councils and statutory bodies like UGC and AICTE, both serving and retired;
- 3.4. Skill training providers recognized by National Skills Development Corporation and / or Sector Skill Councils in their respective area for skills education and training;
- 3.5. NRIs and PIOs working with overseas academic, research and business organizations or having a demonstrated interest in Indian issues.
- 3.6. Skilled professionals working in organized and unorganized sectors known for their hands-on skilling techniques and expertise.

4. Engagement Modalities:

4.1. Qualifications:

Candidate for adjunct faculty should satisfy the following norms:-

a) *For Conventional Higher Education Courses:*

- i) Should have the minimum qualifications as prescribed in the regulations framed by UGC / respective statutory councils from time to time. **OR**
- ii) A person of eminence with or without a postgraduate or Ph.D. qualifications.

b) *For Skill based Courses:*

- i) Should be an accomplished professional / expert in his chosen field of discipline and may not necessarily possess qualifications prescribed under UGC regulations. **OR**
- ii) Should be a certified professional, for teaching and training on National Occupational Standards under NSQF, by the Sector Skills Council for teaching respective trade / job role.

They are also expected to have an understanding of industry requirements, National Occupational Standards (NOSs) and Assessment & Certification for skills.

In addition to the above, it is expected that the adjunct faculty in both the above streams would be an accomplished scholar in his area of specialization and his association would add value to the academic programmes he is associated with.

4.2. Selection Criteria:

Adjunct Faculty will be appointed by the competent authority based on the recommendation of a Committee. Period of empanelment will vary from 06 months to 03 years as decided by the Institution on mutually agreed terms and conditions. It is expected that any application for adjunct faculty is first discussed at the department level. The department may forward the application with comments specifying the suitability of such candidate(s) in the department / institution level academic activities. If the department recommends a case for adjunct faculty, the same should be examined by a Committee comprising of following :

- i) Head of the Institution or his nominee(Chair).
 - ii) Head of the concerned Department.
 - iii) Dean (Academic / Research) in case of university / senior most faculty in case of college.
 - iv) One External Expert (Nominated by head of the institution).
- OR**
- Representative of Sector Skill Council / Industry Associations (for skill based courses).
- v) Registrar / Vice-Principal / Bursar or equivalent person (Convener).

If the committee recommends the case, the same would be forwarded to the competent authority for consideration and necessary approval. The strength of Adjunct faculty may not exceed 25 % the sanctioned strength of faculty at any time.

5. Roles and Responsibilities:

The empanelled adjunct faculty is expected to undertake following assignments:

5.1. Teaching:

- i) **Conventional Higher Education Courses:** Adjunct faculty will be expected to teach courses directly related to his specific expertise and professional experience or the areas of his specialization. He may also contribute to the institution's activities like counseling of students, developing new course(s) and pedagogical improvements.
- ii) **Skill based Vocational Courses:** The core courses pertaining to specialized skills / trades may be imparted by the adjunct faculty from industry, Sector Skill Councils approved trainers or other persons with appropriate skill proficiency. Such faculty, imparting education and training to learners in skill based courses, should have relevant NSQF qualifications, preferably certified by the relevant Sector Skill Council.
- iii) **Research Courses:** Adjunct faculty may also be involved in the M.Phil / Ph.D. coursework based on his professional and research proficiency adjudged by the concerned institution.

5.2. Training: Adjunct faculty will be expected to facilitate the setting of workshops and labs, providing hands on training in the relevant domain areas, development of soft skills, and focus on ensuring competency based learning outcomes among students.

5.3. Research: Adjunct faculty is expected to interact with and supervise the research students in the area of his specialization or professional proficiency. However, there should be preferably one core faculty member associated as Supervisor / Co-supervisor for smooth induction and coordination of academic procedures. The adjunct faculty may lack a traditional academic background in such case, they are not expected to contribute to the institution's research and creative mission by participating in traditional scholarly activities (*i.e.* they are not expected to conduct independent research and/or publish in peer-reviewed journals). Instead, he may participate by advising faculty on their research projects, serving as a liaison between the institutions and industry or government entities to identify research and/or funding opportunities or by working with faculty to identify research projects that would benefit private industry and/or government entities.

5.4. Services: Adjunct faculty is also expected to actively participate in service-related activities, such as sitting on departmental committees, serving as advisors to faculty

and/or undergraduate and post graduate students, helping students network, and active collaboration with the industry / employer providing internship and job opportunities.

6. Costs and Honorarium :

- 6.1. Adjunct faculty will be provided travel cost, as per entitlement, from his/her institution/place of stay and back, maximum six (06) times per academic year. No reimbursement for hiring accommodation will be permissible. However, she/he will be provided free lodging and boarding in the Guest House.
- 6.2. She/he will be provided an honorarium of Rs. 1000/- (Rs. One Thousand Only) per lecture to a maximum of Rs. 4000/- (Rs. Four Thousand Only) per day of service subject to a maximum ceiling of Rs. 80,000/- (Rs. Eighty Thousand Only) per month. The Adjunct Faculty will work at the host institution for a minimum of 02 days per visit.

7. Monitoring :

At the end of assignment, every Adjunct Faculty will submit a 'performance report' to the host university / college with a copy to the University Grants Commission. The performance report, may be considered for his continuation / renewal of next tenure.
